राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2381/2008/बीकानेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, बीकानेर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रवि ट्रेडर्स, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
वी.के.पारीक, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 28/09/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, बीकानेर ने उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 55/आरवैट/बीकानेर/07–08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त–बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 के अन्तर्गत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार करते हुए अस्वीकृत आई.टी.सी. एवं ब्याज राशि रूपये 12,85,777/– को अपास्त किया है, जिसे इस अपील के जरिये चुनौती दी गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी एवं मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से वेट इनवॉइस के जरिये माल क्रय किया जाकर वेट अदा किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने इस पर रूपये 11,10,761/– का आई.टी.सी. क्लेम किया था, जो कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी एवं मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी फर्जी एवं बोगस फर्म हैं तथा उनके द्वारा जारी वेट इनवॉयस फर्जी हैं जबकि अपीलार्थी द्वारा किए गए संव्यवहार के समय विक्रेता फर्म चालू स्थिति में थी तथा उनके कर निर्धारण अधिकारी ने उसका पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 01.04.2006 से

लगातार..............2

निरस्त किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार का इन्द्राज अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में किया गया है एवं विक्रेता ने उससे अलग से वेट चार्ज किया है तथा इनवॉइस पर टिन नं. दर्ज हैं। जब माल क्रय किया गया था तब विक्रेता पंजीकृत था। विक्रेता को भुगतान भी चैक के जरिये किया गया था। केवल एक इस आधार पर आई.टी.सी. नहीं देना कि की गई खरीद बोगस है, अनुचित है। अतः क्रेता के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने की प्रार्थना की। बहस में आगे कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने बोगस फर्म से माल खरीदा है जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया जा चुका है। विक्रेता फर्म ने बेचे गये माल पर कर जमा नहीं कराया है ऐसी स्थिति में आई.टी.सी. का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बहस के अन्त में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी एवं मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से रूपये 3,28,70,741/– की ग्वार एवं चने की खरीद की जाकर इस पर रूपये 11,10,761/– की राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया। जांच पर पाया गया कि मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, फलौदी एवं मैसर्स राकेश ट्रडिंग कम्पनी, फलौदी द्वारा फर्जी क्रय बताकर विक्रय के वैट इनवॉइस जारी किया जाना पाये जाने के फलस्वरूप उक्त दोनों फर्मों के पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निरस्त किये गये है तथा रूपये 11,10,761/– की आई.टी.सी. का दावा अस्वीकृत किया गया है।

6. आलौच्य अवधियों में जिन तथाकथित विक्रेता व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की राशि पर देय वेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, उनकी जांच में उक्त फर्मे या तो अस्तित्व में नहीं पायी गयी अथवा उनका पंजीयन प्रमाण–पत्र भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाना पाया गया। वेट अधिनियम की धारा 18(2) के तहत आई.टी.सी. का क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो एवं यह

लगातार..............3

प्रमाणित करने का दायित्व व्यवहारी का है कि देय कर राजकोष में जमा हो चुका है। प्रत्यर्थी व्यवहारी खरीदे गये माल पर कर चुकाये जाने के सबूत के भार का निर्वहन करने में असफल रहा है।

7. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या किसी क्रेता व्यवहारी की खरीद पर क्लेम की गई आई.टी.सी. के दावे को विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिक्री पर कर जमा नहीं कराये जाने तथा बिक्री संव्यवहार वास्तविक (Genuine) नहीं होने की स्थिति में स्वीकार किया जाने योग्य है अथवा अस्वीकार किये जाने योग्य है ?

8. आई.टी.सी. क्लेम के संबंध में धारा 10, 18(2)(3) का अध्ययन आवश्यक है। उक्त धाराएं निम्न प्रकार है–

10. Burden of proof. –

The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person.

18. Input Tax Credit. –

(1) ....

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –

(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub–section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

लगातार..............4

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

9. उक्त धाराओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को आई.टी.सी. क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा जिन विक्रेता व्यवहारियों से माल क्रय किया जाना दर्शाया गया है, वे अस्तित्वहीन हैं व केवल 'बिल ट्रेड' करके Paper Transaction घोषित किये हैं। जो क्रय बिल प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें एवं विक्रेता व्यवहारियों के बिलों में अन्तर है। ऐसी स्थिति में देय कर राजकोष में जमा होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः व्यवहारी धारा 18(2) व (3) के तहत आई.टी.सी. क्लेम का अधिकारी नहीं रहता है। इसी प्रकार धारा 61(2) के तहत कर निर्धारण अधिकारी आई.टी.सी. के गलत क्लेम के लिये देय कर की चार गुणा तक शास्ति आरोपित करना आवश्यक हैं।

10. इसी प्रकार Non-Obstante Clause के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फुल बैंच के निर्णय **(2006) 148 एस.टी.सी. 356 भदौरिया ग्राम सेवा संस्थान बनाम सहायक आयुक्त, सेल्स टैक्स, इलाहाबाद व अन्य** में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :–

> "Having given our anxious considerations to the various submissions made by the learned counsel for the parties, we find that Section 7-D which provides for composition of tax liability, starts with **a non-obstante clause.** A plain reading of Section 7-D of the Act shows that an option has been given to a dealer who is covered by a scheme issued by the State Government from time to time to opt for payment of lump sum amount in lieu of the amount of tax. It excludes the applicability of other provisions of the Act which deals with the assessment and payment of tax. **A non-obstante clause, as observed by the Apex Court in the case of State of Bihar v. Bihar M.S.K.K. Mahasangh and others, AIR 2005 SC 1605, is generally appended to a section with a view to give the enacting part of the section, in case of a conflict, an overriding effect over the provision in the same or other Act mentioned in the non-obstante clause. It is equivalent to saying that in spite of the provisions or Act mentioned in the non-obstante clause, the provision following it will have its full operation or the provisions embraced in the non-obstante clause will not be an impediment for the operation of the enactment or the provision in which the non-obstante clause occurs.**

लगातार..............5

11. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण–पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त **(1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा** में निम्न निर्णय पारित किया गया है :–

> "Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in Secretary of State for India v. Faredoon Jijibhai Divecha 5, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. **Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government.**

12. इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 66 वी.एस.टी. 75 यू.एस.ए. एजेंसीज व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी अत्तुर (ग्रामीण)** में निम्न निष्कर्ष दिया है :–

> "After extracting the quote from "Maxwell on The Interpretation of Statutes", 10th Edition at page 381 and observing that it is for the Court to ascertain the real intention of the Legislature by carefully examining the scope of Statute, in AIR 1961 SC 751 [State of U.P. and others v. Babu Ram Upadhya], the Hon'ble Supreme Court held as under:-

"29. The relevant rules of interpretation may be briefly stated thus: When a statute uses the word 'shall', prima facie, it is mandatory, but the Court may ascertain the real intention of the legislature by carefully attending to the whole scope of the statute. For ascertaining the real

लगातार..............6

intention of the Legislature the Court may consider, inter alia, the nature and the design of the statute, and the consequences which would follow from construing it the one way or the other, the impact of other provisions whereby the necessity of complying with the provisions in question is avoided, the circumstance, namely, that the statute provides for a contingency of the non-compliance with the provisions, the fact that the non-compliance with the provisions is or is not visited by some penalty, the serious or trivial consequences that flow therefrom, and, above all, whether the object of the legislation will be defeated or furthered."

13. इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अधिकार निहित अधिकार या अलोप्य अधिकार नहीं है, लेकिन अधिनियम के अधीन एक प्रदत्त लाभ है जो विशेष संभाव्यता या विशेष शर्तों के अधीन प्रदत्त किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का अधिकार पंजीकृत व्यवहारियों को निरपेक्ष प्रदत्त व अलोप्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

14. यह (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वास्तव में एक लाभ या अनुग्रह है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रियायती प्रावधानों का अर्थ बहुत कठोरता से लगाया जाना चाहिये। विधि का सुस्थापित नियम है कि कोई व्यक्ति जो मुक्ति या रियायती दर का दावा करता है, के द्वारा आज्ञापक विधिक अपेक्षायें यथावत पूर्ति की जानी चाहिये। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का प्रयोग करने की रियायती अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर Cascading effect of tax burden में कमी के लिये दिया गया है। मूल्य परिवर्धित कर ढांचे का उद्देश्य प्रक्रिया का सरलीकरण करके तथा अधिक पारदर्शी व्यवस्था करते हुए राजस्व में वृद्धि करने का रहा है।

15. इस सन्दर्भ में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **65 वी.एस.टी.सी. 260 जायम एण्ड कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त (सी.टी.)** में पैरा 20 में वेट लागू करने की अवधारणा का उल्लेख निम्न प्रकार है :–

".....The White Paper circulated by the Empowered Committee of State Finance Ministers furnished the following rationale for the introduction of VAT:

"In the existing sales tax structure, there are problems of double taxation of commodities and multiplicity of taxes, resulting in a **cascading tax burden.** For instance, in the exiting structure, before a commodity is produced, inputs are first taxed, and then after the commodity is produced with input-tax load, output is taxed again. This causes an unfair double taxation with cascading effects.

लगातार...............7

In the VAT, a set-off is given for input tax as well as tax paid on previous purchases. In the prevailing sales tax structure, there is in several States also a multiplicity of taxes, such as turnover tax, surcharge on sales tax, additional surcharge, etc. With introduction of VAT, these other taxes will be abolished. In addition, Central sales tax is also going to be phased out. As a result, overall tax burden will be rationalised, and prices in general will also fall. **Moreover, VAT will replace the existing system of inspection by a system of built-in self-assessment by the dealers and auditing. The tax structure will become simple and more transparent. That will improve tax compliance and also augment revenue growth. Thus, to repeat, with the introduction of VAT, benefits will be as follows:**

- a set-off will be given for input tax as well as tax paid on previous purchases
- other taxes, such as turnover tax, surcharge, additional surcharge, etc., will be abolished.
- overall tax burden will be rationalised.
- prices will be self-assessment by dealers
- transparency will increase
- there will be higher revenue growth"

In order to examine the controversy raised in these writ petitions and to test the validity of the impugned provision, a birds eye view of the design of the VAT Act, its concept, coverage, the compulsory requirement to be complied with and other relevant details has to be looked into."

"......Therefore, the net effect of the VAT system is to rationalise the tax burden and bring down in general the price level, stop the tax rate war, and with a view to bring in **simplicity and transparency in the tax structure thereby improving the tax compliance and eventually to ensure growth the revenue. The above in broad terms is the concept of VAT."**

" "Input tax credit", which is in the nature of the concession or indulgence, could be availed only in the manner prescribed under Section 19. The law is well settled that the person, who claims exemption or concessional rate, must obey and fulfil the mandatory requirements exactly. Unless there is strict compliance with the provisions of the statute, the registered dealer is not entitled to claim input tax credit.

लगातार...............8

16. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **(2014) 76 वी.एस.टी. 451 (गुजरात) मैसर्स श्रीजी इम्पेक्स बनाम स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य** में आई.टी.सी. के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> "The claim of input-tax credit on the alleged purchase made by the appellant-dealer from vendors was rejected by the assessing authority considering the fact that the registration of the vendors from whom the appellant claimed to have purchased the goods was cancelled. The assessing officer held that that the appellant failed to prove the actual movement of the goods from the vendors to the appellant. Appeal filed before the first appellate authority was dismissed and the Tribunal dismissed the appeal filed before it confirming the orders passed by both the authorities below denying the input-tax credit. On further appeal:
>
> Held, dismissing the appeal, that input-tax credit was not denied solely on the ground that the registrastion of the vendors was cancelled. The appellant relied upon the invoices/bills and its books of profit and loss in support of the claim that it actually purchased the goods from L and three other vendors. Not a single document and/or material was placed on record to show the actual movement of the goods from the vendors to the appellant. The appellant miserably failed to prove the actual transaction by leading the cogent evidence and miserably failed to prove that purchases on which input-tax credit was claimed, were genuine and/or on which the tax was paid. There were concurrent findings of fact given by all the authorities below that the alleged transactions were not genuine and it was only billing activities for the purpose of claiming input-tax credit, etc. The aforesaid findings of facts by all the authorities below were on appreciation of evidence and the material on record which were neither perverse nor contrary to the evidence on record. Therefore no error had been committed by any of the authorities below denying the input-tax credit."

17. इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में व्यवस्था दी गयी है कि –

(1) [2014] 73 VST 489 (Guj) Karnavati Ispat Pvt. Ltd. vs. State of Gujarat and Another

VALUE ADDED TAX-INPUT-TAX CREDIT-DENIAL ON GROUND OF CAN-CELLATION OF REGISTRATION OF SELLING DEALER AB INTIO-SELLING DEALER FOUND NOT TO BE CARRYING ON GENUINE PURHASE AND SALE BUT ONLY DOING BILLING-DENIAL OF INPUT-TAX CREDIT JUSTIFIED-GUJARAT VALUE ADDED TAX ACT, 2003.

–लगातार..............9

The assessing officer denied the input-tax credit claimed by the appellant-dealer on the goods purchased on the ground that the registration of the selling dealer was cancelled ab initio because it was only billing and did not carry out any genuine transactions of sale and purchase. The order denying input-tax credit and levy of interest thereon was confirmed by the Tribunal while remanding the matter to the assessing officer in respect of the levy of penalty at the highest limit. On appeal:

Held, dismissing the appeal, that the order of the Tribunal was justified.

(2) **[2014] 73 VST 129 (Tel. and AP) Vijaya Venkata Durga Oil Traders vs. Commercial Taxes Officer, Sivalayam Street Circle, Vijayawada I Division, Vijayawada and Another**

VALUE ADDED TAX-WRITS UNDER CONSTITUTION-INPUT-TAX CREDIT-DEALER PURCHASING EDIBLE OILS FROM OUTSIDE STATE AND SELLING THEM TO DEALERS WITHIN STATE-INTER-STATE PURCHASES SUPPRESSED AND DOCUMENTS CREATED TO ESTABLISH LOCAL PURCHASES-SELLING DEALERS FOUND NOT CARRYING ON BUSINESS-WHERE-ABOUTS OF PROPRIETORS NOT KNOWN -TAX INVOICES SHOWING GOODS NOT PURCHASED DIRECTLY FROM THOSE DEALERS BUT THROUGH AGENTS AT P-TAX INVOICES NOT SHOWING BRANCH OF SELLING DEALERS AT P-PAYMENT MADE NOT AT REGISTRED PLACE OF BUSINESS OF SELLING DEALERS BUT TO BRANCH ACCOUNT AT P-CONCLUSION THAT DEALERS HAD NOT SUPPLIED GOODS TO DEALER NOR MADE PAYMENT TO THEM AND TRANSACTIONS WERE CREATED ONLY TO CLAIM BENEFIT OF INPUT-TAX CREDIT-CONCLUSION NEITHER BASED ON NO EVIDENCE NOR FINDINGS PERVERSE-COURT WILL NOT INTERFERE IN WRIT JURISDICTION-CONSTITUTION OF INDIA, ART 226-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX ACT (5 of 2005), SS. 13(1), 21(3), (5)-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX RULES, 2005, r. 25.

VALUE ADDED TAX-INPUT-TAX CREDIT-TAX INVOICE-DOES NOT PRECLUDE POWER OF ASSESSING AUTHORITY TO ASCERTAIN WHETHER TRANSACTIONS GENUINE-IF ON ENQUIRY NO SALE FOUND TO HAVE TAKEN PLACE OR TAX INVOICE FOUND NOT ISSUED BY DEALER OR NO PHYSICAL DELIVERY OF GOODS FOUND OR INTER-STATE PURCHASES FOUND SUPPRESSED AND BOGUS TAX INVOICES RAISED-ASSESSING OFFICER MAY

लगातार..............10

DENY INPUT-TAX CREDIT-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX ACT (5 of 2005), S. 13.

ASSESSMENT-LIMITATION-EXTENDED PERIOD IN CASE OF WILFUL EVASION OF TAX-ALLEGATIONS IN SHOW-CAUSE NOTICE AND FINDINGS RECORDED IN ASSESSMENT ORDER MUST ESTABLISH WILFUL EVASION-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX ACT (5 of 2005), SS. 13(1), 21(3), (5)-ANDHRA PRADESH VALUE ADDED TAX RULES, 2005.

NATURAL JUSTICE-PRINCIPLES OF-AUDI ALTERAM PARTEM-WHEN OPPORTUNITY TO CROSS-EXAMINE WITNESSES TO BE GRANTED.

WRITS UNDER CONSTITUTION-NATURE OF JURISDICTION OF COURT-NOT APPELLATE-COURT WILL. NOT DISTURB FINDINGS OF FACT-CONSTITUTION OF INDIA, art. 226.

(5) [2014] 72 VST 318 (Guj) Madhav Steel Corporation vs. State of Gujarat

(ii) That the dealer had failed to satisfy the court as to the genuineness of the sale transactions or purchases made from B and M by leading evidence or prove on the basis of the documents on record that there was movement of goods. Even the vendors B and M had also failed to prove their purchases and no goods were available with them which could have been sold to the dealers and in fact there was no physical movement of the goods. The onus to prove the genuineness of the purchase was on the dealer. The onus to prove the genuineness of the purchase of the vendor from whom the dealer made purchases was also on the dealer. The assessing officer and the Tribunal had rightly rejected the claim to input-tax credit claimed under section 11 of the Act.

18. उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रय संव्यवहार फर्जी हैं। विक्रेता ने कर जमा नहीं कराया है। विक्रेता का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया।

28/01/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य